



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कृषि उत्पादन में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की भूमिका का अध्ययन - इंदौर जिले के सन्दर्भ में

Jyoti Jaiswal

Research scholar,

School of Economics, Devi Ahilya University, Indore,

M. Vasim khan

Assistant professor (senior Grade),

School of Economics, Devi Ahilya University, Indore,

सारांश

इंदौर जिला कृषि औद्योगिक प्रदेश में सबसे बड़ा नगर है, जो म.प्र. के पश्चिमी भाग में और मालवा के पठार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र अधिक शहरी और औद्योगिकृत है। वर्तमान अध्ययन में इंदौर जिला तथा इंदौर जिले के पाच तहसीलों के 300 कृषकों का अध्ययन किया गया। कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण का स्तर निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में श्रेष्ठ है। कृषि से संबंधित 8 प्रमुख सरकारी योजनाओं की जागरूकता और लाभार्थी कृषकों की संख्या को इंदौर जिले के 5 तहसीलों में देखा गया। जिसमें से तीन योजनाएँ - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएम किसान सम्मान निधि योजना (P.M.K.S.N.) और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का प्रयोग इंदौर जिले के सभी तहसीलों के किसानों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तहसीलवार अध्ययन में इंदौर और महु तहसील में योजनाओं की जागरूकता और हितग्राही कृषकों की संख्या सर्वाधिक देखी गई। और कृषि योजना के जागरूकता और हितग्राही कृषकों के मध्य सकारात्मक उच्च सहसम्बन्ध (79%) पाया गया है।

Keywords: किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि योजना, सहसम्बन्ध, आधुनिकीकरण

परिचय :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% आबादी कृषि और उससे सम्बंधित कार्यों में लगी है। और CSO के अनुसार वर्ष 2016-17 में कृषि और सम्बंधित क्षेत्रों का योगदान गिरकर 17.4 % रह गया है। आज देश में खेती का योगदान कुल अर्थव्यवस्था में 14% के लगभग होने पर भी इससे करीब 60% लोगों को रोजगार मिल रहा है। खेत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर है, जो लगातार जनसंख्या की वृद्धि के साथ घट रहा है। कुल भू स्वामित्व का 75% कृषक लघु और सीमान्त कृषक है। छोटे किसान की प्रधानता वाला देश जिसमें कृषकों की दशा आज भी दयनीय है। वर्तमान समय में देश में उपलब्ध कुल 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि के क्षेत्रफल में देश लगभग 16.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जो कुल भूमि क्षेत्रफल का 49.80%

है। वही राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान 23.36% है, और फसल क्षेत्र में 3.66% की वृद्धि हुई, समग्र रूप से कुल खाद्यानों के क्षेत्रफल में 7.39% की वृद्धि परिलक्षित हुई। और खाद्यान फसलो के उत्पादन में गतवर्ष से 32.33 % की वृद्धि हुई। (म. प्र. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21)

आधुनिकीकरण के युग में कृषि में आधुनिकता को बरकरार रखने के लिए सरकार समय समय पर किसानों और कृषि की उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ तथा नीतियाँ बना रही है तथा उन्हें कार्यान्वित भी कर रही है। नीतियाँ निश्चित रूप से किसानों की सामाजिक दशा और आर्थिक स्थिति में सुधार करती है, और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ जैसे बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा जाच कार्ड तथा विपणन जैसे प्रक्रिया में सहयोग कर किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास करती है।

म प्र सरकार द्वारा भी निम्न प्रकार की नीतियाँ तथा योजनाएँ प्रदेश के किसानों के लिए चलाई गईं, और कुछ मुख्य नीतियाँ और योजनाएँ प्रदेश के किसान के लिए प्रभावशाली सिद्ध हुईं, इसी सन्दर्भ में कुछ मुख्य योजनाओं का इंदौर जिले के तहसीलों में कृषकों के मध्य प्रभाव का अध्ययन किया गया।

साहित्य की समीक्षा

- **अरिहंत समसामयिकी महासागर नामक पत्रिका** प्रकाशित संस्करण अगस्त 2013 में कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान के प्रतिशत का उल्लेख करते हुए एवं भारत की जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता के प्रतिशत का वर्णन करते हुए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई कृषि बीमा योजनाओं को प्रकाशित करते हुए कहा है कि भारत के कुल जनसंख्या के लगभग 58% लोग कृषि कार्यों में कार्यरत हैं, तथा भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 14% है, अतः इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद भी भारतीय कृषि एवं कृषक अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। इन सब समस्याओं से बचने तथा एक बड़े वर्ग को भविष्य के प्रति आशान्वित रखने के लिए बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- **कुरुक्षेत्र नामक पत्रिका** के प्रकाशित संस्करण फरवरी 2009 में महेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा लिखित शोध पत्र विषय शीर्षक " किसानों के संरक्षण के लिए योजनाएँ के अंतर्गत शोधार्थी ने किसान काल सेंटर, किसान चैनल योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, MSP BPL कार्ड आदि का उल्लेख करते हुए किसानों के समस्या के समाधान सम्बन्धी उपाय सुझाये हैं ताकि कृषि भी लाभकारी व्यवसाय याँ रोजगार की श्रेणी में आ जाये और किसान भुखमरी के शिकार न हो।
- **अनीता मोदी (2004) "सूचना तकनीकी से बदलती गावों की दुनिया"** में लिखा है कि आज के दौर में ग्रामीण और कृषकों के पास सूचना प्राप्त करने के माध्यम हैं। कृषि मंत्रालय ने किसानों को कृषि से जुड़ी किसी भी समस्या का हल बताने के उद्देश्य से किसान काल सेंटर की शुरुआत की गई है। वर्तमान में देश भर के कई किसान इसका इस्तेमाल कर लाभान्वित हो रहे हैं।
- **बलवीर सिंह और कुसुम वास्केल (2012) "ग्रामीण म.प्र. में महिला रोजगार और ग्रामीण विकास"** पर लेख लिखते हुए कहा कि म.प्र. में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करने के लिए समय-समय पर नीतियों का निर्माण किया है। जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना, महिला डेयरी परियोजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, महिला स्वयं सिद्ध योजना आदि। परन्तु शोधकर्ता द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया और पाया कि इतनी योजनाओं के बाद भी महिलाओं के जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया।
- **Prabha R.goyal, Bindu naik, Ray and Ram singh ने जनवरी 2016 में role of government schemes in Indian agriculture and rural development** विषय पर अध्ययन द्वितीयक आकड़ों के माध्यम से किया। मुख्य रूप से अध्ययन में पहली से लेकर बारहवी तक पंचवर्षीय योजना और कृषि से सम्बन्धित सरकार के द्वारा चलाये गये कार्यक्रम और नीतियाँ, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, रूरल गो डाउन स्कीम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग आदि का प्रभाव देखने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष में बताया कि नीतियाँ जिस वर्ग के लिए होती हैं, वास्तव में उन तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए एक विधिवत क्रिया होनी चाहिए, तभी सरकार के द्वारा किये गये प्रयास सफल सिद्ध हो सकते हैं।
- **Venu B.N., Umesh K.B & Olekar के द्वारा नवम्बर 2016 में Impact of government schemes on availability of agricultural labours in the Karnatka state, India an economic analysis** पर लेख प्रकाशित किया। अध्ययन का केंद्र बिंदु सरकारी नीतियों से श्रमिक की पूर्ति तथा मजदूरी दर से श्रमिक की पूर्ति पर प्रभाव क्रॉस सेक्शन आकड़ों से की गई।

म प्र के बीजापुर जिले के 60 कृषि श्रमिक और 40 किसान को सैंपलिंग के रूप में लिया और आकड़ों को विश्लेषित ओसतन वार्षिक लाभ सरकारी कार्यक्रम से किया गया। निष्कर्ष में बताया की श्रमिक कृषक द्वारा श्रम की आपूर्ति के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव के सापेक्ष माग की आय लोच बड़ी है ।

- **Taufiq Ahmad & Rifat haneef (2018) में Government agricultural scheme in India : A review** विषय पर अध्ययन किया, अध्ययन का सार ये था की भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए अधिक प्राथमिकता दे रही है। इस सम्बन्ध में यह कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए कई किसान कल्याण योजनाओं को लागू कर रहा है । इसलिए किसान ने सभी किसानों को लाभान्वित करने के लिए नई पहल योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किये हैं ।

उपरिकल्पना

H0: किसानों के सरकारी योजनाओं की जागरूकता और हितग्राही के मध्य किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है।

मुख्य उद्देश्य

- इंदौर जिले में तहसीलवार सरकारी योजनाओं के जागरूकता का अध्ययन
- इंदौर जिले में प्रभावशाली योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

शोध क्रियाविधि

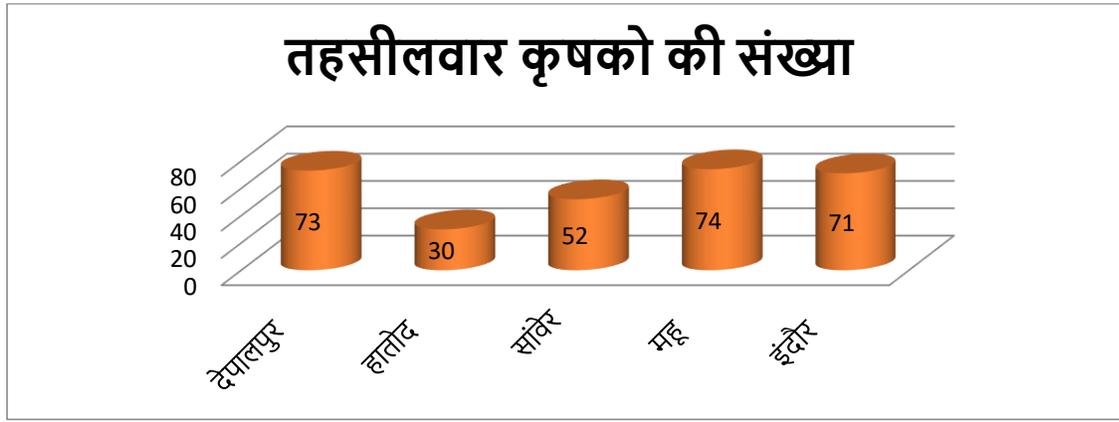
- खोजपूर्ण अनुसन्धान के माध्यम से प्राथमिक से प्राथमिक स्रोत का संकलन इंदौर जिले के तहसीलों में किया गया । इंदौर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 382.2 हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि 264.2 हेक्टेयर, वन क्षेत्रफल 52.2 हेक्टेयर, गैर कृषि के तहत भूमि 27.2 हेक्टेयर है, और इस जिले की फसल सघनता 165.1% है । बहुस्तरीय नमूना विधि का उपयोग के साथ साथ कृषकों का चयन कोटा और डेल्टा विधि के माध्यम से किया गया है । जिसकी सहायता से इंदौर जिले के पाँच तहसील में से गावों का चयन किया गया। इस प्रकार इंदौर जिले के प्रत्येक तहसील की जनसंख्या के अनुपात में कृषकों की संख्या का निर्धारण किया गया।

$$S = \frac{z^2 P(1 - P)}{e^2}$$

सूत्र का प्रयोग करते हुए देपालपुर से 73, सांवेर से 52, हातोद से 30 , महु से 74 और इंदौर से 71 इस प्रकार कुल 300 कृषक का प्रतिचयन आकार है।

1. आकड़ों को विश्लेषित करने की विधियाँ: इंदौर जिले में तहसीलवार सरकारी योजनाओं के जागरूकता के अध्ययन को प्रतिशत और पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और इंदौर जिले में प्रभावशाली योजनाओं का अध्ययन के लिए काई स्क्वायर और सहसंबंध का प्रयोग किया गया।

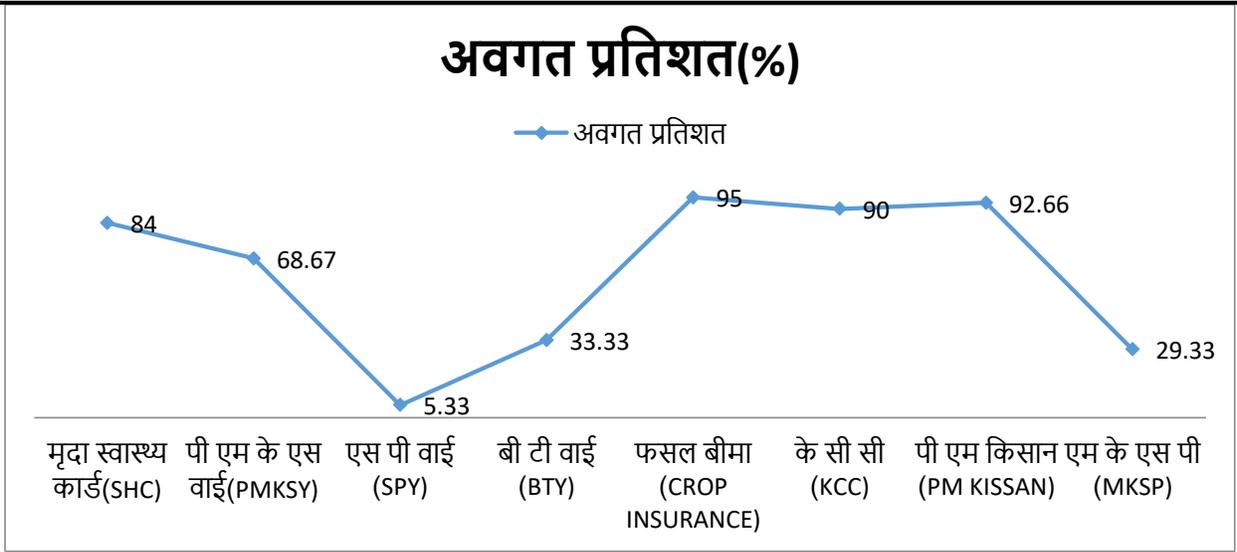
तालिका क्र 1



2. इंदौर जिले में प्रमुख योजनाओ की जागरूकता

तालिका क्र 2

क्र.	योजनाओ के नाम	अवगत आवृत्तिया (Aware frequency)	अवगत प्रतिशत (Aware percent)	अनवगत आवृत्तिया (Unaware frequency)	अनवगत प्रतिशत (Unaware percent)
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड(SHC)	252	84.00	45	16.00
2	पी एम के एस वाई(PMKSY)	206	68.67	93	31.33
3	एस पी वाई (SPY)	16	05.33	239	94.66
4	बी टी वाई (BTY)	100	33.33	198	66.67
5	फसल बीमा (CROP INSURANCE)	285	95.00	13	05.5
6	के सी सी (KCC)	270	90.00	25	10.00
7	पी एम किसान (PM KISSAN)	278	92.66	22	07.33
8	एम के एस पी (MKSP)	88	29.33	211	70.67



उपर्युक्त ग्राफ में किसानों द्वारा 8 प्रमुख कृषि योजनाओं की जागरूकता के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है जिसमें फसल बीमा योजना की सर्वाधिक जागरूकता और सौर पंप योजना की सबसे निम्न जागरूकता इंदौर जिले के कृषकों के मध्य है।

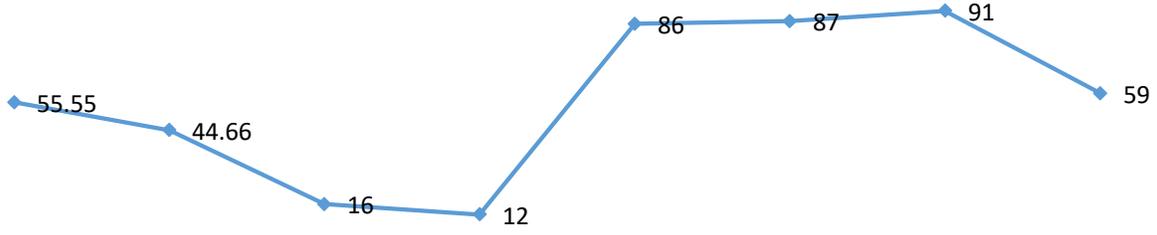
3. जागरूकता के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी कृषकों की संख्या

तालिका क्र. 3

क्र.	योजनाओं के नाम	अवगत प्रतिशत	हितग्राही प्रतिशत
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड(SHC)	84.00	55.55
2	पी एम के एस वाई(PMKSY)	68.67	44.66
3	एस पी वाई (SPY)	05.33	16
4	बी टी वाई (BTY)	33.33	12
5	फसल बीमा (CROP INSURANCE)	95.00	86
6	के सी सी (KCC)	90.00	87
7	पी एम किसान (PM KISSAN)	92.66	91
8	एम के एस पी (MKSP)	29.33	59

हितग्राही प्रतिशत (%)

— हितग्राही प्रतिशत



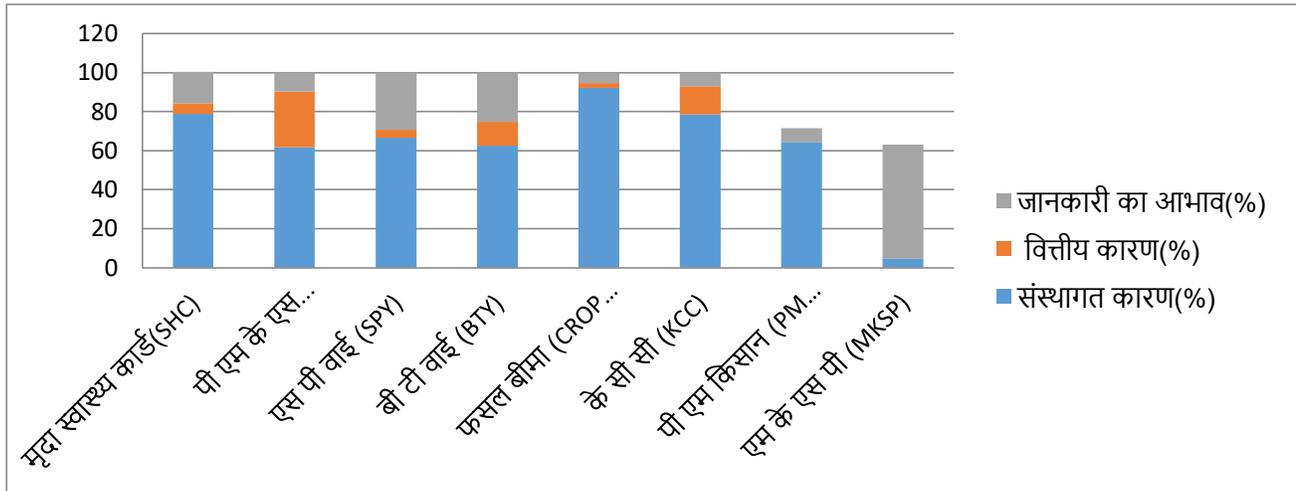
मृदा स्वास्थ्य कार्ड(SHC) पी एम के एस वाई(PMKSY) एस पी वाई (SPY) बी टी वाई (BTY) फसल बीमा (CROP INSURANCE) के सी सी (KCC) पी एम किसान (PM KISSAN) एम के एस पी (MKSP)

उपर्युक्त ग्राफ में योजनाओं के जागरूकता के प्रतिशत में से हितग्राही कृषक के प्रतिशत को दर्शाया गया है। जिसमें उपरोक्त तालिका में अध्ययन में पाया गया था कि फसल बीमा की जागरूकता सर्वाधिक है, परन्तु इसका प्रयोग सिर्फ 86% कृषको द्वारा ही किया जा रहा है। वही पी एम किसान सम्मान निधि योजना का प्रयोग 91% कृषको द्वारा किया जा रहा है।

4. किसानों का योजनाओं से वंचित रहने के कारण

तालिका क्र. 4

क्र	योजनाओं के नाम	संस्थागत कारण (%)	वित्तीय कारण (%)	जानकारी का आभाव (%)
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड(SHC)	78.78	5.5	16.16
2	पी एम के एस वाई(PMKSY)	61.60	28.7	9.82
3	एस पी वाई (SPY)	66.66	4.16	29.16
4	बी टी वाई (BTY)	62.66	12	25.33
5	फसल बीमा (CROP INSURANCE)	92.10	2.63	5.26
6	के सी सी (KCC)	78.57	14.28	7.14
7	पी एम किसान (PM KISSAN)	64.28	-	7.14
8	एम के एस पी (MKSP)	4.72	-	58.36



उपर्युक्त दंड आरेख के माध्यम से बताया गया है की योजनाओ के लाभ और जानकारी से वंचित रहने के मुख्य तीन कारण है। जानकारी का आभाव, वित्तीय कारण और संस्थागत कारण। शेष कृषक जो योजनाओ की जानकारी से वंचित है, का महत्वपूर्ण कारण संस्थागत कारण है, और उसके पश्चात जानकारी का आभाव और वित्तीय कारण है।

तहसीलवार सरकारी योजनाओ के लाभार्थियों का प्रतिशत

तालिका क्र. 5

क्र.	योजनाओ के नाम	देपालपुर (%)	हातोद (%)	इंदौर (%)	महू (%)	सावेर (%)
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड(SHC)	43.75	55.55	67.92	56.89	56
2	पी एम के एस वाई (PMKSY)	28.57	38.88	75	34.42	37.5
3	एस पी वाई (SPY)	12	25	18.75	8.33	23.80
4	बी टी वाई (BTY)	13.79	0	11.76	12	13.63
5	फसल बीमा (CROP INSURANCE)	79.41	81.48	89.85	92.85	86.27
6	के सी सी (KCC)	70.76	72	93.65	98	90
7	पी एम किसान (PM KISSAN)	83.07	96.42	95.52	99	84.31
8	एम के एस पी (MKSP)	58.33	62.05	28.57	61.90	76.19

उपर्युक्त तालिका में तहसीलवार योजनाओं के हितग्राही कृषक का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया की इंदौर तहसील मूदा कार्ड और पी एम कृषि सिंचाई योजना का प्रयोग सर्वाधिक करता है, वही फसल बीमा, के सी सी और पी एम किसान सम्मान निधि के सर्वाधिक हितग्राही महु तहसील में है।

सहसंबंध: सरकारी योजनाओं का जागरूकता और हितग्राही के मध्य सम्बन्ध का परिक्षण सहसम्बन्ध के माध्यम से किया गया।

संक्षिप्त विवरण

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
जागरूकता * हितग्राही	8	100.0%	0	.0%	8	100.0%

कृषको का प्रमुख 8 सरकारी योजनाओं में जागरूकता और हितग्राही के मध्य सहसंबंध ($\alpha = 0.05$)

		जागरूकता	हितग्राही
जागरूकता	Pearson Correlation	1	.798*
	Sig. (2-tailed)		.018
	N	8	8
हितग्राही	Pearson Correlation	.798*	1
	Sig. (2-tailed)	.018	
	N	8	8

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5% सार्थकता स्तर पर जागरूकता और हितग्राही के मध्य सहसंबंध 79% है। इस प्रकार हम

$r (AW, AV) = 0.79$, जहा AW - जागरूकता, AV - हितग्राही तथा r सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित करता है। यहा Z टेबल के सार्थकता स्तर 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पर क्रांतिक मान (critical value) सहसंबंध स्तर 0.706 है, जो गणना के मान (0.798) से कम है, अतः उपपरिक्ल्पना H0 को अस्वीकार, और H1 को स्वीकार करता है, अर्थात् r सहसंबंध सार्थक है, और योजनाओं की जागरूकता और हितग्राही के मध्य सकारात्मक सांख्यिकीय सम्बन्ध पाया जाता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि इंदौर जिले के पाच तहसीलों के 300 किसानों के अध्ययन में पाया गया की 8 महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं में 3 सर्वाधिक अवगत प्रतिशतता वाली योजनाये- फसल बीमा (95%), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (92.66%) और किसान क्रेडिट कार्ड (90%) है, जिनके हितग्राही अवगत कृषको का क्रमशः 86%, 91% तथा 87% कृषक है।

इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ लेने में असमर्थता के तीन प्रमुख कारण को अध्ययन के दौरान सम्मिलित किया गया, यथा- संस्थागत कारण, वित्तीय कारण और जानकारी का आभाव।

इनमें संस्थागत कारण सर्वाधिक प्रभाव डालता है। जैसे फसल बीमा योजना , किसान क्रेडिट कार्ड योजना तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में संस्थागत कारण कुल वंचित कृषको का क्रमशः 92.10%, 78.57% तथा 78.78% को लाभ लेने में असमर्थ करता है ।

तहसीलवार योजनाओं के लाभार्थी कृषक की संख्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इंदौर तहसील की क्रमशः 67.92%, और 75% है। सौर पंप योजना के सर्वाधिक हितग्राही सावेर तहसील में लगभग 25% कृषक है। बलराम ताल योजना के सर्वाधिक लाभार्थी देपालपुर में 13.79% है, वही फसल बीमा , किसान क्रेडिट कार्ड और पी एम किसान सम्मान निधि योजना का प्रयोग महु तहसील के क्रमशः 92.85%, 98% और 99% कृषको द्वारा किया जा रहा है, और महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के सर्वाधिक लाभार्थी सावेर तहसील में अर्थात् 76.19% है।

अध्यन के परीक्षण में पाया गया कि कुल कृषको का 79% कृषक ऐसे भी है जिन्हें योजनाओं की जानकारी भी है और उनका लाभ भी ले रहे है।

Refrence

- Agrawal, Umeshchandra (December 1999). Kurukshetra patrika. Report.
- Arihant Samsmayikee patrika report (August 2013).
- Prabha R.goyal, Bindu naik, Ray and Ram singh (January 2016). “role of government schemes in Indian agriculture and rural development”
- Venu B.N., Umesh K.B & Olekar (November 2016). “Impact of government schemes on availability of agricultural labours” Karnatka, India an economic analysis.
- Ministry of Agriculture (2019), Agricultural Statistics at a glance, New Delhi: Government of India.
- All India Report on Agriculture Census (2015-16) Department of agriculture, cooperation & farmers welfare: ministry of agriculture.